42 Chapter

ज्ञान कॉमन्स: विकसित भारत 2047 के लिए उत्प्रेरक के रूप में पुस्तकालय

सीमा कुमारी[1], श्रद्धा कल्ला[2], नंदन सिंह[3] सोनू राठौर[4]

[1]सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष, आईआईएचएमआर, विश्वविद्यालय, जयपुर
[2]पुस्तकालयाध्यक्ष,आईआईएचएमआर, विश्वविद्यालय, जयपुर
[3]सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष, आईआईएचएमआर, विश्वविद्यालय, जयपुर
पुस्तकालयाध्यक्ष, भवानी निकेतन कॉलेज, जयपुर

Summary

आज के समय में पुस्तकालय केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रह गए हैं। वे ऐसे सक्रिय और जीवंत केंद्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं जहाँ लोग एकत्र होते हैं, विचारों का आदान-प्रदान करते हैं तथा सूचना तक समान और लोकतांत्रिक पहुँच प्राप्त करते हैं। पुस्तकालय आजीवन अधिगम को बढ़ावा देने, समुदायों को जोड़ने और सभी वर्गों के लिए अवसरों के द्वार खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भारत के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में पुस्तकालय न्यायसंगत शिक्षा, डिजिटल पहुँच, अनुसंधान नवाचार और सशक्त समुदायों के लिए प्रभावी साधन के रूप में उभरते हैं। यह शोधपत्र ज्ञान-आधारित समाज के निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का विश्लेषण करता है, भविष्य की चुनौतियों एवं अवसरों को रेखांकित करता है तथा पुस्तकालयों को सक्रिय ज्ञान केंद्रों में रूपांतरित करने हेतु व्यावहारिक नीतियाँ और कार्यनीतियाँ प्रस्तुत करता है, जिससे भारत के राष्ट्रीय विकास को गति मिल सके।

Keywords: ज्ञान कॉमन्स, पुस्तकालय, डिजिटल समावेशन, आजीवन अधिगम, विकसित भारत 2047, सूचना तक पहुँच, सामुदायिक सशक्तिकरण

परिचय

भारतीय परिप्रेक्ष्य में विकसित भारत 2047 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा, नवाचार और ज्ञान तक सभी की समान पहुँच हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति में पुस्तकालयों की भूमिका केंद्रीय है। अब पुस्तकालय केवल पुस्तकों के भंडार नहीं रहे, बल्कि वे ऐसे मंच बन गए हैं जो लोगों को जोड़ते हैं, नए विचारों को जन्म देते हैं और ज्ञान को समाजोपयोगी बनाते हैं।
समय के साथ-साथ पुस्तकालयों का स्वरूप व्यापक रूप से बदला है। आज वे डिजिटल संसाधनों, सामुदायिक कार्यक्रमों, मेकर-स्पेस तथा अनुसंधान उपकरणों से युक्त हैं। यह परिवर्तन वैश्विक प्रवृत्तियों—जैसे मुक्त पहुँच (Open Access), सहयोगात्मक अधिगम और सामुदायिक विकास—के अनुरूप है। यह शोधपत्र भारत में पुस्तकालयों की उस परिवर्तनकारी भूमिका का अध्ययन करता है जिसके माध्यम से डिजिटल कौशल विकास, अनुसंधान सहयोग और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

वैचारिक ढाँचा: ज्ञान कॉमन्स क्या हैं?

ज्ञान कॉमन्स का तात्पर्य है—
• ऐसा साझा संसाधन तंत्र जहाँ सूचना और सांस्कृतिक सामग्री का सामूहिक रूप से सृजन, संरक्षण और उपयोग किया जाता है।
• जो सामुदायिक मानदंडों, पारदर्शिता, स्थिरता और समान पहुँच की नीतियों द्वारा संचालित होता है।
• जो प्रौद्योगिकी, मानव नेटवर्क और संस्थागत सहयोग से सशक्त होता है।

पुस्तकालय ज्ञान कॉमन्स के लिए आदर्श मंच हैं क्योंकि वे—
• सूचना तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करते हैं।
• सहयोगात्मक एवं आजीवन अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं।
• डिजिटल और सामाजिक समावेशन हेतु सामुदायिक आधार केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

पुस्तकालय और राष्ट्रीय विकास: विकसित भारत 2047 से संबंध
शिक्षा और आजीवन अधिगम पुस्तकालय औपचारिक शिक्षा से आगे बढ़कर—
• विद्यालय, विश्वविद्यालय और वयस्क शिक्षार्थियों के लिए अधिगम संसाधन उपलब्ध कराते हैं।
• साक्षरता, समालोचनात्मक चिंतन और व्यावसायिक कौशल पर कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं।
• अनुसंधान और पाठ्यक्रम सुदृढ़ीकरण हेतु शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करते हैं।

डिजिटल समावेशन और प्रौद्योगिकी तक पहुँच तेजी से डिजिटल हो रहे समाज में डिजिटल असमानताएँ बनी हुई हैं। इस संदर्भ में पुस्तकालय—
• निःशुल्क इंटरनेट, कंप्यूटर और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं।
• ग्रामीण और वंचित समुदायों को डिजिटल शासन प्रणालियों से जोड़ सकते हैं।
• ई-गवर्नेंस, ई-स्वास्थ्य और ऑनलाइन सेवाओं के केंद्र के रूप में कार्य कर सकते हैं।

अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र पुस्तकालयों में ज्ञान कॉमन्स नवाचार को बढ़ावा देते हैं—
• मुक्त पहुँच रिपॉजिटरी और अनुसंधान डेटाबेस उपलब्ध कराकर।
• विश्वविद्यालयों, स्टार्ट-अप्स और उद्योग के साथ साझा अनुसंधान मंचों पर सहयोग करके।
• मेकर-स्पेस, डेटा लैब और अंतःविषय सहयोग क्षेत्रों की स्थापना करके।

सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक समानता पुस्तकालय सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करते हैं—
• पांडुलिपियों, स्थानीय इतिहास और पारंपरिक ज्ञान का डिजिटलीकरण करके।
• भारत की भाषाई विविधता को प्रतिबिंबित करने वाले बहुभाषी संसाधनों को बढ़ावा देकर।
• समावेशी और सुलभ शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करके।

चुनौतियाँ और बाधाएँ

आधारभूत संरचना की कमी
• ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त ब्रॉडबैंड और डिजिटल सुविधाएँ।
• पुराने भौतिक ढाँचे जो सामुदायिक सहभागिता को सीमित करते हैं।

वित्तीय और नीतिगत सीमाएँ
• आधुनिकीकरण हेतु सीमित बजट आवंटन।
• केंद्र और राज्य स्तर पर खंडित नीतिगत समर्थन।

कौशल अंतर और क्षमता निर्माण
• डिजिटल पुस्तकालय विज्ञान में पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकता।
• डेटा विज्ञान, मुक्त पहुँच प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता में कौशल की कमी।

सामग्री उपलब्धता और लोकभाषा तक पहुँच
• क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सामग्री की कमी।
• लाइसेंसिंग, कॉपीराइट और ओपन एक्सेस से जुड़ी चुनौतियाँ।

पुस्तकालयों को ज्ञान कॉमन्स में रूपांतरित करने की रणनीतिक रूपरेखा

नीतिगत अनुशंसाएँ
1. राष्ट्रीय पुस्तकालय नवाचार कोष – डिजिटल अवसंरचना, क्षमता निर्माण और सामुदायिक पहुँच के लिए समर्पित कोष।
2. एकीकृत पुस्तकालय नेटवर्क – सार्वजनिक, शैक्षणिक और विशेष पुस्तकालयों को साझा मंच से जोड़ना।
3. मुक्त पहुँच और डिजिटल रिपॉजिटरी – सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान के लिए ओपन एक्सेस अनिवार्य करना।

4. क्षेत्रीय भाषा सामग्री पहल – प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री का विकास।

डिजिटल और सामुदायिक अवसंरचना
• ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड विस्तार।
• आधुनिक हार्डवेयर, क्लाउड और सहयोगी उपकरणों की उपलब्धता।

क्षमता निर्माण और पेशेवर विकास
• डिजिटल पुस्तकालय विज्ञान, डेटा क्यूरेशन और ज्ञान प्रबंधन में राष्ट्रीय कार्यक्रम।
• विश्वविद्यालयों और अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क के साथ साझेदारी।

सामुदायिक सहभागिता मॉडल
• स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सेवाओं का सह-डिज़ाइन।
• कौशल विकास और नागरिक सहभागिता हेतु लाइब्रेरी लर्निंग सर्कल की स्थापना।

केस स्टडी और श्रेष्ठ अभ्यास

भारत में डिजिटल पुस्तकालय पहल
• राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय भारत (NDLI) – एकीकृत पहुँच का उत्कृष्ट उदाहरण।
• राज्य स्तरीय डिजिटल साक्षरता अभियानों में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका।

वैश्विक मॉडल
• नॉर्डिक देशों के सार्वजनिक पुस्तकालयों में सार्वभौमिक डिजिटल पहुँच।
• विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में मेकर-स्पेस द्वारा अनुसंधान नवाचार।

प्रभाव का मूल्यांकन

ज्ञान कॉमन्स के रूप में पुस्तकालयों के आकलन हेतु निम्न संकेतकों को अपनाया जा सकता है—
• डिजिटल समावेशन संकेतक (इंटरनेट पहुँच, उपयोगकर्ता सहभागिता)
• अधिगम परिणाम और कौशल उन्नयन
• सामुदायिक सहभागिता और सह-सृजन
• अनुसंधान दृश्यता और मुक्त पहुँच अपनाने की दर

निष्कर्ष

विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के संदर्भ में यह आवश्यक है कि पुस्तकालयों को अतीत की धरोहर के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र के ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र की सशक्त धुरी के रूप में पहचाना जाए। पुस्तकालय अपने पारंपरिक स्वरूप से आगे बढ़कर खुलेपन, सामुदायिक सहभागिता और डिजिटल सशक्तिकरण पर आधारित समावेशी ज्ञान कॉमन्स के रूप में विकसित हो सकते हैं, जिससे सूचना की समान पहुँच सुनिश्चित होगी तथा नवाचार और सामाजिक लचीलापन सुदृढ़ होगा।

संदर्भ

1. UNESCO. Public Libraries and Innovating Futures.
2. Ostrom, E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action.
3. National Digital Library of India (NDLI) Framework.
4. Government of India. Vision 2047: Strategic Roadmap for Development.

43 Chapter

भारत में ONOS पहल: अकादमिक पुस्तकालयों की रणनीति और योगदान

Shraddha Kalla[1], Sushila Bisht[2], Seema Kumari[3], Nandan Singh[4]

[1]Librarian, IIHMR University, Jaipur, Rajasthan India
[2]Librarian Bansal Public School, Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan India
[3]Assistant Librarian IIHMR University, Jaipur, Rajasthan India
[4]Assistant Librarian IIHMR University, Jaipur, Rajasthan India

Summary

डिजिटल युग में शैक्षणिक एवं शोध सूचना तक पहुँच किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति का आधार बन चुकी है। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में तीव्र वृद्धि के बावजूद सभी संस्थानों को समान गुणवत्ता वाली विद्वतापूर्ण सूचना तक पहुँच उपलब्ध नहीं है। इसी असमानता को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा *वन नेशनल वन सब्सक्रिप्शन* पहल की परिकल्पना की गई है। यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख शैक्षणिक प्रकाशकों के ई-जर्नल्स और डेटाबेस के लिए एकीकृत सब्सक्रिप्शन मॉडल प्रदान करती है। इस शोध-पत्र में ONOS पहल की अवधारणा, उद्देश्य और ढाँचे का विश्लेषण करते हुए अकादमिक पुस्तकालयों की रणनीतिक भूमिका और योगदान को रेखांकित किया गया है। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि अकादमिक पुस्तकालय न केवल सूचना संसाधनों के प्रदाता हैं, बल्कि नीति कार्यान्वयन, उपयोगकर्ता प्रशिक्षण, तकनीकी समर्थन और सूचना समानता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, पेपर में चुनौतियों, भविष्य की संभावनाओं तथा पुस्तकालय-आधारित सिफ़ारिशों पर भी चर्चा की गई है।

Keywords: ONOS, अकादमिक पुस्तकालय, डिजिटल सूचना संसाधन, सूचना समानता, ई-जर्नल्स, भारत

भूमिका

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के तीव्र विकास ने शैक्षणिक और शोध परिदृश्य को पूर्णतः बदल दिया है। आज उच्च गुणवत्ता वाला शोध मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, डेटाबेस, ई-बुक्स और डिजिटल रिपॉजिटरी पर निर्भर करता है। परंतु भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में संसाधनों की लागत, लाइसेंसिंग नीतियाँ और संस्थागत आर्थिक सीमाएँ सूचना पहुँच में असमानता उत्पन्न करती हैं। अकादमिक पुस्तकालय परंपरागत रूप से ज्ञान के संरक्षक रहे हैं, किंतु डिजिटल युग में उनकी भूमिका सूचना प्रबंधक, प्रशिक्षक और नीति समर्थक के रूप में विस्तृत हो गई है। ONOS पहल इसी परिवर्तनशील भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करती है।

ONOS पहल की अवधारणा और उद्देश्य

वन नेशनल वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) पहल का मूल विचार यह है कि देश के सभी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित उच्च शिक्षण और शोध संस्थानों के लिए विद्वतापूर्ण ई-संसाधनों का **एकीकृत राष्ट्रीय लाइसेंस** उपलब्ध कराया जाए।

प्रमुख उद्देश्य

- शैक्षणिक सूचना तक समान और सार्वभौमिक पहुँच
- संस्थानों पर आर्थिक बोझ में कमी